क्षेत्रीय समाचार एकांश

देहरादून (उत्तराखण्ड)

गुरुवार 03.07.2025

समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश के सभी जिलों में गुरुकुल पद्धति पर आधारित संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे।
- लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को मानसून सीजन में सजग और तत्पर रहने के निर्देश दिए।
- राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने कहा– आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कुंभ से जुड़े सभी स्थायी और अस्थायी कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए।

<u>संस्कृत शिक्षा प्रोत्साहन</u>

प्रदेश के सभी जिलों में गुरुकुल पद्धति पर आधारित संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए संस्कृत विभाग ठोस प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंपेगा। इसके साथ ही आश्रम पद्धति के तर्ज पर दूरस्थ क्षेत्रों में आवासीय संस्कृत विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। संस्कृत महाविद्यालयों के सही वर्गीकरण और शिक्षकों को समय पर पदोन्नति देने के लिए अधिनियम–2023 में संशोधन किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत को जन–जन की भाषा बनाने के लिए पिछड़े विकासखंडों में भी आश्रम पद्धति आधारित विद्यालयों की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलसचिव की नियुक्ति, बीएड पाठ्यक्रम और परीक्षा भवन निर्माण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

मॉनसून सतर्कता

लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को मानसून सीजन में सजग और तत्पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान सड़कों के अवरुद्ध होने से यात्रियों को भारी परेशानी होती है, ऐसे में मार्गों को शीघ्रता से खोलना विभागों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

देहरादून स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में श्री महाराज ने कहा कि अगर अधिकारी सजगता से काम करें तो मानसून का समय बिना अवरोध पार किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि बंद सड़कों की सूचना यात्रियों को समय रहते दी जाए ताकि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकें।

लोक निर्माण मंत्री ने मलबा हटाने वाली मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता, नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बैठक में मैदानी क्षेत्रों में जल भराव और बाढ़ के खतरे को देखते हुए ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। सिंचाई विभाग ने बताया कि सभी जिलों में नोडल बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए जा चुके हैं और देहरादून में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित है। राज्य में 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और 304 संवेदनशील स्थलों की पहचान कर ली गई है। नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है और सभी अधिकारी हर वक्त मोबाइल पर उपलब्ध हैं।

बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित

चमोली जिले में देर रात हुई भारी बारिश के चलते में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग और उममा के समीप यातायात के लिये बाधित हो गया है। लगातार हो रही बारिश और इससे हो रहे भूस्खलन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली दर्जनों सड़कें बंद हैं। जिला प्रशासन की ओर से सभी सड़कों को खोलने का कार्य जारी है।

नाराजगी

चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों में लागत बढ़ने पर गहरी नाराजगी जताई है। दून मेडिकल कॉलेज में हरिद्वार, रुद्रपुर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावत ने कार्यदायी संस्थाओं और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए।

बैठक में कार्यदायी संस्थाओं ने निर्माण कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया, लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने लागत में बार–बार बढ़ोतरी को अनुचित ठहराते हुए कहा कि यह प्रथा बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाते समय भवन निर्माण मानकों का पालन करते हुए सटीक आकलन किया जाना चाहिए और अनुबंध के अनुसार समय पर कार्य पूरे किए जाएं।

बैठक में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए 200 नाली अतिरिक्त भूमि खरीदने और कॉलेज–चिकित्सालय को जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। डॉक्टर रावत ने यह भी कहा कि जिन मेडिकल कॉलेजों और छात्रावासों के भवन बन चुके हैं, उन्हें विधिवत रूप से हैंडओवर कर लिया जाए।

विशेष सहयोग की मांग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दिल्ली–देहरादून एलिवेटेड रोड के शुरू होने के बाद राज्य में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार नियोजन की चुनौती पर अभी से सक्रियता से काम कर रही है। ट्रैफिक समस्या और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र से 26 किलोमीटर लंबी रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए अनुरोध किया है। साथ ही पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये नीति आयोग से विशेष ग्रांट की मांग की है।

देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। राज्य एसडीजी इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है और देश में जीईपी लागू करने वाला पहला राज्य भी बना है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य की साढे छह हजार एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है।

आयुष्मान भारत

आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को मरीजों की सुविधा के लिए अब कई जरूरी बदलाव करने होंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक वार्ड में योजना का टोल फ्री नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए, ताकि मरीज या उनके परिजन किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत संपर्क कर सकें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कई बार लाभार्थियों से धन वसूली या भ्रम फैलाने की शिकायतें मिलती हैं, जिन पर रोक जरूरी है। इसके लिए अस्पतालों को आयुष्मान योजना से संबंधित जानकारी के डिस्प्ले बोर्ड भी लगाने होंगे, जो हिंदी और स्थानीय भाषा में हों।

बैठक में बताया गया कि अस्पताल परिसरों में आईसीयू के निकट वेटिंग रूम की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। कतारों से निजात दिलाने के लिए टोकन डिस्प्ले, प्रतीक्षा कक्ष की उचित व्यवस्था और मरीज के फीडबैक फार्म को भी अनिवार्य किया गया है।

श्रीमती जोशी ने सभी अस्पतालों से इन निर्देशों के अनुपालन की जानकारी तय समयसीमा में देने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समीक्षा/कुंभ तैयारियां

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि कुंभ से जुड़े सभी स्थायी और अस्थायी कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। कार्यों की समयसीमा को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों से तय समय में काम पूरा करने को कहा गया है।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों की शीघ्र नियुक्ति और प्रमुख स्नान पर्वों के अनुसार श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या के आधार पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीड़ के अनुसार घाटों की संख्या भी बढ़ाई जाए और मेलाधिकारी सभी हितधारकों से लगातार संवाद बनाए रखें।

बैठक में कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर ए, बी और सी श्रेणियों में बांटने और जरूरी कार्यों को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर विभागों को भूमि आवंटित की जानी है, वहां से अतिक्रमण हटाया जाए और कुंभ मेला क्षेत्र से सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही हो। इस दौरान हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक को 20 अगस्त 2025 तक यातायात और पार्किंग की योजना मेलाधिकारी को सौंपने के निर्देश दिए गए।

मीडिया बातचीत

ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि उत्तराखंड फार्मा हब के रूप में तेज़ी से उभर रहा है, लेकिन कुछ बाहरी तत्व यहां की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कालानी ने देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में बनने वाली दवाएं गुणवत्ता मानकों के अनुसार तैयार की जाती हैं और बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात भी होती हैं।

उन्होंने बताया कि हाल में जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, वे नकली नहीं, बल्कि तकनीकी कमियों के कारण फेल हुए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय लैब की जांच रिपोर्ट आने से पहले दवाओं को नकली न बताया जाए, क्योंकि इससे कंपनी की ब्रांड और छवि को नुकसान पहुंचता है।

एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि अधिकांश मामलों में सैंपल पीएच अंतर, डिसइंटीग्रेशन या लेबलिंग की त्रुटियों के कारण फेल होते हैं, न कि गुणवत्ता में कमी के कारण। महासचिव संजय सिकारिया ने बताया कि ऐसी तकनीकी कमियों की पुष्टि के लिए कोलकाता स्थित सेंट्रल लैब में पुनः जांच जरूरी होती है।

ट्रॉली सुविधा

टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक के चिफल्डी गदेरे में पीडब्ल्यूडी थत्यूड़ द्वारा ट्रॉली सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। दोनों ओर एबटमेंट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यहां ट्रॉली सेवा एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ कर दी जाएगी। इससे ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

पूर्व में यहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 30 मीटर स्पान वाले स्टील पुल का निर्माण प्रस्तावित था। हालांकि, अगस्त 2024 में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण निर्माणाधीन पुल को भारी क्षति पहुंचा था। नदी की चौड़ाई बढ़ने और मलबा जमा होने के कारण यह पुल अनुपयोगी हो गया।

इसके बाद योजना में संशोधन करते हुए अप्रैल 2025 में 48 मीटर स्पान के नए पुल की स्वीकृति प्राप्त हुई। वर्तमान में पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस पुल के मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में जेसीबी या अन्य असुरक्षित साधनों से नदी पार न करें। ट्रॉली सेवा प्रारंभ न होने तक केवल ह्यूम पाइप मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर.......

जिला पंचायत सदस्य के लिए भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशी — इस शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है — उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, नामांकन के पहले दिन 2 हजार 167 लोगों ने भरा पर्चा।

आपदा प्रबंधन में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी, 522 सखी होंगी तैयार। दैनिक जागरण की ख़बर है। समाचार पत्र के अनुसार— मुख्यमंत्री धामी अपने कार्यकाल के पांचवे वर्ष में इस योजना को करेंगे लॉन्च।

उत्तराखंड के हर जिले में खुलेगा गुरुकुल पद्धति विद्यालय— अमर उजाला इस शीर्षक के साथ लिखता है समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश।

नरेंद्रनगर के पास कैंटर पलटने से तीन श्रद्धालुओं की मौत की ख़बर पर हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है— कांवड़ियों के लिए भंडारा शिविर लगाने गंगोत्री जा रहे थे श्रद्धालु, हादसे में 18 लोग घायल, सीएम धामी ने जताया दुख।

और, उत्तराखंड के मौसम की खबर पर हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने लिखा है— देहरादून समेत 4 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी।